IJAER/ March-April 2023/Volume-12/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन की भूमिका नियामक बाधाएँ: चुनौतियों का समाधान करने के उपाय

प्रिया कुमारी मिश्रा

शोधार्थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सोध सार

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन की भूमिका बहुआयामी है। भारत अपने अनेकता और विविधता के लिए प्रसिद्ध है, कृषि एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता है। यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन एक कुंजीपथ है जो न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि समृद्धि और समृद्धिक विकास की दिशा में भूमिका निभाता है। कृषि विपणन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार सृष्टि करता है और लोगों को आर्थिक समृद्धि के साधन के रूप में उपयोग होता है। हालांकि, इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ और नियामक बाधाएँ हैं जिन्हें हमें समाधान करना होगा। खेत से कृषि उत्पादों को खरीदने, बेचने और ग्राहक तक वितरित करने की प्रक्रिया को कृषि विपणन कहा जाता है। इसमें बिचौलियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है, जिसमें कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ शामिल हैं, जो सभी कृषि वस्तुओं की आवाजाही में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अनुसंधान लेख में, हम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन के महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

कीवर्ड: कृषि विपणन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समृद्धि, समृद्धिक विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार

प्रस्तावना:

कृषि क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ग्रामीण भारत में आर्थिक समृद्धि का मौद्रिक रूप मुख्यत: कृषि विपणन के माध्यम से हो रहा है। इस अनुसंधान लेख में, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन के सामने आने वाली चुनौतियों और समृद्धि के संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सिर्फ भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या का रोजगार कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। हालांकि, वर्तमान समय में भारतीय कृषि क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है। सिंचाई सुविधाओं की कमी, मानसून पर निर्भरता, किसानों की आय में कमी, छोटे और सीमांत जोतों की समस्या, बाजार और अवसंरचना की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी और तकनीकी की कमी, व्यावसायिक भावना की कमी, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक खादों का उपयोग - इन सभी कारणों से धारणीय कृषि संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को मध्यस्थता करते हुए, 2017-18 के बजट में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हजारों किसानों को रोजगार प्रदान करता है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का सातवाँ स्थान और क्रय शक्ति समता की दृष्टि से तीसरा स्थान रखने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा असंगठित व्यवसाय है और यह निर्देशिका का क्षेत्र है जो राष्ट्रीय आय का स्रोत, रोजगार और जीवनयापन का मुख्य साधन है। इसलिए स्वतंत्रता से पूर्व भी, कृषि विकास के प्रयास जारी रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को महत्वपूर्ण माना गया है। महात्मा गांधी ने सही कहा था, "भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।" इसलिए, गाँवों के विकास से ही देश का विकास संभव है, जिससे साफ है कि कृषि विकास से ही देश का विकास संभव है।

अध्ययन का उद्देश्य: अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन के महत्व का अध्ययन करना है।

परिकल्पना - किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और इससे केवल भोजन और कच्चे माल की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि इससे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए भी संभावना होती है। कृषि और उद्योग परस्पर निर्भर करते हैं और एक क्षेत्र के विकास से दूसरे क्षेत्र का भी विकास होता है। एक क्षेत्र के विकास से दूसरे क्षेत्र को अधिक आगतों का प्रवाह होता है और इससे निर्भरता बढ़ती है। कृषि का महत्व उसकी सहायता के साथ बढ़ता है, और यह दोनों क्षेत्रों की निर्भरता का सारांश होता है। जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है, तो कृषि की भूमिका में भी परिवर्तन आता है। कुछ समय के बाद, जब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विकास होता है, तो कृषि की महत्ता कम हो जाती है। इसके बावजूद, कृषि क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ती है और इससे साझा बाजारों का विकास होता है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, और बिना कृषि के आधुनिकीकरण के, औद्योगिक विकास संभावना नहीं है। इसलिए, कृषि विकास के बिना आर्थिक विकास संभावना नहीं है। बिना औद्योगिकरण के कृषि विकास भी संभावित नहीं है। इसलिए, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों का साथ-साथ विकास होना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कृषि ग्रामीणों आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो रोजगार प्राप्त करने का साधन, ग्रामीण उद्योगों के लिए आधार, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कुंजी के रूप में कार्य करता है। कृषि कैसे ग्रामीणों को अपने विकास के लिए सामर्थ्यपूर्ण बना सकती है, इस पर अध्ययन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था दो मुख्य क्षेत्रों, अर्थात (1) कृषि क्षेत्र और (2) गैर-कृषि क्षेत्र, के मिलन से बनी है। पहले में खाद्य और व्यावसायिक फसलें शामिल हैं, जबकि दूसरे में ग्रामीण गतिविधियों में पशुपालन, डेयरी, मुर्गा पालन, मत्स्य पालन, और वन्यजन समाहित हैं। जब किसान बेरोजगार होते हैं, तो इन गतिविधियों से जुड़कर वे अल्प बेरोजगारी को कम करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत गाँवों में निवास करता है, और 10 में से 7 व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। भारत में 6 लाख 40 हजार 930 गाँव हैं और गाँवों में साक्षरता का प्रतिशत 67.8 प्रतिशत है, जिसमें 57.9 प्रतिशत स्त्रियाँ और 77.2 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं। इसके अलावा, भारत में कुल श्रमिकों का 54.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबंधित व्यावसाय में लगा है। इसलिए, आज भी भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बना हुआ है, जिसमें कई कारण हैं।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका

कृषि विपणन लाखों लोगों के लिये, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्रोत प्रदान करता है। किसान, व्यापारी, मजदूर और परिवहन कर्मचारी सभी अपनी आजीविका कृषि विपणन प्रणाली से प्राप्त करते हैं। यह कृषि उपज के लिये उचित मूल्य निर्धारित करने में सहायता करता है, जिससे किसानों को अपने निवेश पर उचित रिटर्न प्राप्त होता है। हालाँकि, वर्तमान विपणन प्रणाली प्राय: किसानों को बिचौलियों की स्वेच्छा पर छोड़ देती है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य के आधार पर शोषण होता है। यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाज़ारों से जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुँचे। इससे फसल बर्बादी कम होती है तथा आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता प्राप्त होती है। कृषि विपणन खाद्य आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुँचे। खाद्य सुरक्षा के लिये एक अच्छी तरह से काम करने वाली विपणन प्रणाली महत्त्वपूर्ण है।

कृषि विपणन में चुनौतियाँ:

विश्वभर में बढ़ती किसान आबादी और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों के सामना करते हुए, कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत और कुशल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस क्षेत्र में कई चुनौतियां आ सकती हैं जो निम्नलिखित हैं:

प्रौद्योगिकी समृद्धि की कमी: भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शीत भंडारण सुविधाओं और गोदामों जैसी उचित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिये इसके परिणामस्वरूप फसल के बाद अत्यधिक हानि होती है। कृषि विपणन में नवाचारी तकनीकों का अभाव है, जिससे उत्पादों को सुरक्षित और गुणवत्ता से बाजार में पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। किसानों को समृद्धि और तकनीकी सुधारों को अपनाने के लिए सहायक संस्थानों की आवश्यकता है।

संगठन की कमी: सही संगठन और समन्वय की अभावना से किसान अपने उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। किसान समूहों को बढ़ावा देने और उन्हें सामूहिक संस्थान बनाने की आवश्यकता है। किसान प्राय:स्वयं को बिचौलियों की स्वेच्छा पर निर्भर होते हैं जो कीमतों में हेर-फेर करते हुए उच्च कमीशन वसूलते हैं। इस शोषण के परिणामस्वरूप किसानों को अंतिम उपभोक्ता मूल्य का न्यूनतम भाग ही प्राप्त होता है।

अद्यतित बाजार जानकारी: समय पर एवं सटीक बाज़ार जानकारी के अभाव में किसानों को अपनी उपज कब और कहाँ बेचनी है, इसके बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे और अधिक अक्षमताएँ जन्म लेती हैं।किसानों के पास बाजार की अद्यतित जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए तकनीकी साधनों और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का उपयोग करके, किसानों को बाजार रहित जानकारी प्रदान करने के लिए नए साधनों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना चाहिए। प्रचलित मूल्य खोज तंत्र प्राय: त्रुटिपूर्ण होते हैं, जिससे किसानों के लिये कीमतें अस्थिर एवं अप्रत्याशित हो जाती हैं। यह अस्थिरता उनकी आय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है।

वित्तीय समर्थन की कमी: कृषि विपणन के लिए उच्च लागतें हो सकती हैं, जो किसानों को वित्तीय समर्थन की आवश्यकता पैदा करती हैं। सरकारों और गैर सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए ताकि किसान उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग और स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान कर सकें।

प्राकृतिक आपातकालीन परिस्थितियाँ: प्राकृतिक आपातकालीन परिस्थितियाँ जैसे कि बाढ़, सूखा, और तूफान कृषि उत्पादों को प्रभावित कर सकती हैं। सुरक्षित परिस्थितियों के लिए कृषि विपणन सुविधाएं तैयार करने में सरकारों को योजनाएं बनानी चाहिए। भारत में कृषि विपणन व्यवस्था विभिन्न नियमों के अधीन है, जो बोझिल और जटिल है। ये नियम अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं साथ ही किसानों एवं व्यापारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों में वृद्धि करते हैं। इससे सामग्री उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक कई अधिकारी और संगठनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, सरकारों को नीतियों में सुधार करना

चाहिए, ताकि कृषि विपणन में नए और सुरक्षित तकनीकों का उपयोग हो सके और किसानों को सहारा मिले। इस प्रकार, हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कृषि विपणन प्रणाली मजबूत, कुशल, और खाद्य सुरक्षित रहती है।

नियामक बाधाएँ: चुनौतियों का समाधान करने के उपाय:

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सुदृढ़ बनाना: FPO किसानों को सामूहिक रूप से उनकी उपज का विपणन करने एवं बेहतर कीमतों पर चर्चा करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारी समर्थन एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रम FPO की प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।

बुनियादी ढाँचे में निवेश: आधुनिक भंडारण सुविधाएँ, परिवहन नेटवर्क और बाज़ार यार्ड विकसित करने से फसल के बाद होने वाली हानि को कम किया जा सकता है साथ ही बाज़ार पहुँच में सुधार किये जा सकता है। किसानों द्वारा उपभोक्ताओं अथव थोक खरीदारों के लिये सीधे विपणन को बढ़ावा देने से बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती है और साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।

बाज़ार सूचना प्रणाली: प्रौद्योगिकी-संचालित बाज़ार सूचना प्रणालियों को लागू करने से किसानों को कीमतों के साथ मांग पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त हो सकती है। e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) जैसी पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। राज्य सरकारों को कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) अधिनियमों में सुधार करना चाहिये ताकि उन्हें अधिक किसान-अनुकूल बनाया जा सके साथ ही कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया जा सके। नीति निर्माताओं को कृषि विपणन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे की समीक्षा के साथ उसका सरलीकरण करना चाहिये ताकि इसे अधिक निवेशक-अनुकूल एवं कुशल बनाया जा सके।

अनुबंध खेती: अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करने से किसानों को मूल्य स्थिरता के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी एवं इनपुट तक पहुँच प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में स्पष्ट अनुबंध और विवाद समाधान तंत्र आवश्यक

हैं। कृषि विपणन सुधार का एक सफल उदाहरण गुजरात में अमूल सहकारी समिति के बारे में है। डेयरी किसानों की सहकारी संस्था के रूप में शुरू हुई अमूल, भारत की सबसे प्रमुख और सफल कृषि विपणन संस्थाओं में से एक बन गई है। एक उल्लेखनीय उदाहरण e-NAM पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाना है। पारदर्शी मूल्य खोज के साथ व्यापार के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके, e-NAM में विपणन प्रणाली की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है।

निष्कर्ष:

कृषि विपणन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो समृद्धि और समृद्धिक विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाता है। इस अनुसंधान लेख ने इस भूमिका के महत्व को समझने के लिए कृषि विपणन के आयामों पर चर्चा की है और इसमें आने वाली चुनौतियों और समाधानों को बताया है। हालाँकि, इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसकी दक्षता तथा किसानों के कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। सुधारों के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे में निवेश तथा प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने से अधिक मज़बूत एवं कुशल कृषि विपणन प्रणाली को जन्म दिया जा सकता है। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा तथा फसल कटाई के बाद के हानि में कमी सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे किसानों, उपभोक्ताओं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र रूप से लाभ प्राप्त होगा। किसानों की आय दोगुनी करने एवं समग्र कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कृषि विपणन सुधार एक आवश्यक कदम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. पंत डी.सी. - भारत में ग्रामीण विकास विश्वभारती पब्लिकेशन्स. नई दिल्ली, 2011
2. डॉ. मिश्र जयप्रकाश - कृषि अर्थशास्त्र साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा,
3. डॉ. पंत जायसी, डॉ. मिश्र जे. पी. भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2015,

4. डॉ. मामोरिया चतुर्भुज, डॉ. जैन एस.सी. - भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2010
5. कृषि का महत्व एवं भूमिका |
6. भारतीय अर्थव्यवस्था,
7. कृषि अर्थशास्त्र,
8. प्रतियोगिता दर्पण 641 प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली, 2014,
9. डॉ. माहेश्वरी पी.डी., डॉ. गुप्ता शीलचन्द्र भारत में आर्थिक पर्यावरण, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2007.
10. www.brainstark.com>Agriculture